भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

Undertaking for due to compliance raised in principal approval

Name of Project: 4 Laning wih Paved Shoulder from Naviganj to Mitrasen Section (Km. 289+000 to 356+000) of NH - 91 (Aligarh - Kanpur) in Kannauj District.

As per the comment's raised in MoEF&CC vide letter no. 8B/UP/6/25/2018/FC/04 dated 05.04.2018, the NHAI has duly complied all the condition-imposedin stage - 1 as well as in stage - 2. However REC raised the concern about the point no.- ix of a MOEF & CC final approval vide file no. F.NO. 8-16/2012-FC dated 9th may 2013 for NH-91.

The NHAI here with undertake that strip plantation will be raised in proposed bypass for package-IV - length 20.28, where in width 7.5m strip on both side of length is available.

Plantation will be carried out as per IRC SP. 21/2009.

(P.P. Singh)
Project Director
Project Director
National Highways Authority of India,
PIU-Aligarh

Scanned by CamScanner

संख्या-1429/14-2-2013

प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ
प्राप्ति सं० 44080
दिनांक 17/8/13

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प०का०इ० अलीगढ़
प्राप्ति संख्या 5885
प्राप्ति दिनांक 29/8/13

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनाँक 16 अगस्त, 2013

विषयः

अलीगढ़ से कानपुर, अलीगढ़, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, कन्नौज तथा कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन०एच०-91 के चौड़ीकरण हेतु 111.64 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्याः1942/11सी-एन०एच०-91, दिनांक 14-5-2013 तत्कम में मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के संलग्न सैद्धांतिक स्वीकृति एफ०नं०-8-16/2012-एफसी, दिनांक 09-5-2013 तथा विधिवत् स्वीकृति एफ०नं०-8-16/2012-एफसी, दिनांक 21-9-2012, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल अलीगढ़ से कानपुर, अलीगढ़, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, कन्नौज तथा कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन०एच०-91 के चौड़ीकरण हेतु 111.64 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तों राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तों का समावेश करते हुये अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1)- भा.स. **Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.**

वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2)- भा.स. **Compensatory Afforesation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency as per plan submitted with the proposal.**

प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव में सम्मिलित योजना के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।

(3)- भा.स. **The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.**

मा० उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार यदि अतिरिक्त वर्तमान वास्तविक मूल्य (NPV) निश्चित की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसका भुगतान करना होगा।

(4)- भा.स. **The User Agency shall maintain the cost of strip plantation on either side of the road and central verge, as per IRC specification,per in-principle approval.**

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर आई आर सी की विशिष्ठयों के अनुरूप व जैसा कि सैद्धांतिक स्वीकृत में अनुमोदित है, के अनुसार प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण एवं केन्द्रीय वर्ज का रख रखाव किया जायेगा ।

(5)- भा.स. **Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval in consultation with the State Forest Department at the project cost.**

जहां तक तकनीकी रूप से सम्भव हो सके प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस अनुमोदन के फलस्वरूप सड़क के किनारे चिन्हित क्षेत्र के वृक्षारोपण एवं वन विभाग के परामर्श से परियोजना की लागत से किया जायेगा।

(6)- भा.स. **The layout plan of the proposal shall not changed without the prior approval of the Central Government.**

प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से बदला नहीं जायेगा।

(7)- भा.स. **Wherever possible and technically feasible shall undertake Afforestation Measures on diverted forest land.**

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक अण्डरटेकिंग देना होगा कि तकनीकी रूप से सम्भव व मानकों के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रत्यावर्तित वन भूमि पर किया जायेगा।

(8)- भा.स. **The NHAI shall provide funds for operation of the nursery raised unde this proposal as per condition no.(viii) of in- principal approval :**

Forest file
30/8/2013

Fresh Receipt
GM/DGM-I/DGM-II/M(F)
27/08 P.D. Aligarh
रा०-15014/3/RO/LKO/2012/
18407, dt 26/08/13
CGM(T)/RO-Lko

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक लाख पौध वार्षिक क्षमता की एक वन नर्सरी स्थापित किया जायेगा, जिस वन प्रभाग से गुजरने वाले सड़क के किनारे स्थानीय ग्रामीणों को घटे दरों पर नर्सरी उगाने हेतु बीच का वितरण कराया गया।

(9)– भा.स. No labour camp shall not be estabished on the forest land.

वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।

(10)– भा.स. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency,department or person.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता अभिकरण के लिये आवश्यक न हो किसी भी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति,संस्था अथवा किसी अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(11)– भा.स. The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/लकड़ी/अन्य कोई वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि समीपस्थ वन क्षेत्र में किसी प्रकार का क्षति न हो।

(12)– भा.स. The boundary of the diverted forest land , shall be demarcated on ground at the project cost , erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंची मजबूत कंकरीट के बाउण्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा। वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनका कमांक तथा पीलर से पीलर की दूरी का भी अंकन किया जायेगा।

(13)– भा.स. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(14)– भा.स. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस परियोजना से फ्लोरा और फौना को कोई नुकसान न हो।

(15)– भा.स. felling of trees on the forest land diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़े कम से कम वृक्षों का पातन राज्य वन विभाग की कड़े पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(16)– भा.स. The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लागत पर वृहद् रूप से मृदा संरक्षण हेतु सुरक्षा उपायों का अण्डरटेकिंग देना होगा।

(17)– भा.स. Any other condition that the addl. PCCF Central Regional Office, Lucknow may stipulate, from time to time, the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife .

भारत सरकार के अधीन सम्बंधित अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित अन्य शर्तो, जो कि वृक्षों एवं वन्य जीवों की संरक्षा,सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(18)– भा.स. The User Agency shall submit the annual compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the Regional Office Lucknow regularly, and .

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तो के अनुपालना की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार और भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

(19)– भा.स. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts,Rules,Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

प्रस्तुत परियोजना हेतु लागू आवश्यक नियमों, विनियमों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन राज्य सरकार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं समस्त उपबन्धों एवं अधिनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(20)– भा.स. The area identified for Compensatory Afforestion shall be clearly depicted on Survey of India toposheet of 1:50000 scale.
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1: 50000 मानक के टोपोशीट मानचित्र पर स्पष्ट रूप से क्षतिपूरक वृक्षारोपण चिन्हित किया जायेगा।

(21)- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(22)- प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन-202/1995 की आई०ए० 566 के अनुसार शासनादेश रिट-526/14-2-08, दिनांक 22-8-2008 के द्वारा निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०),क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुश्रवण देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(23)- प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उसके कर्मचारी के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(24)- उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(25)- वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उनके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(26)- प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ०प्र० वन निगम द्वारा ही किया जाएगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, लॉगिंग लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के उपान का खर्च प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफ०सी० दिनांक 11-12-08 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(27) प्रयोक्ता अभिकरण को यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि एन०पी०वी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है, इसका भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(28) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-Fc (Pt), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है, तो (if applicable),कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(29) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(30) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(31) प्रस्तावक से यह अपेक्षा है कि परियोजना में जितने वृक्षों को कटने से बचाया जा सकता है, उनको बचा लिया जाये।

(32) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा०न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1429(1)/14-2-2013-तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर, एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- महालेखाकार-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
5- जिलाधिकारी, अलीगढ, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, कन्नौज तथा कानपुर।
6- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, कन्नौज (फर्रुखाबाद) तथा कानपुर।
7- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ए-215 यमुनापुरम, बुलन्दशहर।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

F. No. 8-16/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110510
Dated: 29th May, 2013

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: Diversion of 111.64 ha of forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for widening of NH 91 from Aligarh to Kanpur in Aligarh, Mahamaya Nagar, Etwah, Mainpuri, Kannauj and Kanpur Districts of Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter no. 569/14-2-2012 dated 28th February, 2012 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and its letter No. 2502/11C dated 06.06.2012 vide which information as desired by the Forest Advisory Committee in its meeting held on 15th May, 2012 was furnished. After careful examination of the proposal on the basis of recommendations of the Forest Advisory Committee (FAC) constituted under Section-3 of the said Act, 'in-principle' approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 21st September, 2012 subject to fulfillment of certain conditions prescribed therein. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter no. 1298/11C-NH-91 dated 12.02.2013, final approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 111.64 ha of forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for widening of NH 91 from Aligarh to Kanpur in Aligarh, Mahamaya Nagar, Etwah, Mainpuri, Kannauj and Kanpur Districts of Uttar Pradesh subject to fulfillment of the following conditions:

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

(ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency as per plan submitted with the proposal;

(iii) The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

(iv) The user agency shall maintain the cost of strip plantation on either side of the road and central verge, as per IRC specification, as per in-principle approval.

(v) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

(vi) The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

(vii) Wherever possible and technically feasible shall undertake Afforestation Measures on diverted forest land.

(viii) The NHAI shall provide funds for operation of the nursery raised under this proposal as per condition no. (viii) of in-principle approval.

(ix) No labour camp shall be established on the forest land;

(x) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.

(xi) The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

(xii) The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

(xiii) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

(xiv) The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area;

(xv) Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;

(xvi) The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost.

(xvii) Any other condition that the Addl. PCCF (Central), Regional Office, Lucknow may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xviii) The user agency shall submit the annual compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the Regional Office, Lucknow regularly; and

(xix) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully,

(B. K. Singh)
Director

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow.
3. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard file.

(B. K. Singh)
Director

13/5

नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक
उ० प्र०, लखनऊ

Forest

F. No. 8-16/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)
***

Paryavaran Bhawan
CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110516
Dated: 21st September 2012

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow

Sub: **Diversion of 111.64 ha of forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for widening of NH 91 from Aligarh to Kanpur in Aligarh, Mahamaya Nagar, Etwah, Mainpuri, Kannauj and Kanpur Districts of Uttar Pradesh- regarding.**

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter no. 2502/11 C dated 6th June 2012 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under section-3 of the said Act.

2 After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the Forest Advisory Committee, the Central Government hereby conveys the 'in-principle' approval for diversion of 111.64 ha of forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for widening of NH 91 from Aligarh to Kanpur in Aligarh, Mahamaya Nagar, Etwah, Mainpuri, Kannauj and Kanpur Districts of Uttar Pradesh subject to fulfillment of the following conditions:

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency; (1)

(iii) The area identified for Compensatory Afforestation shall be clearly depicted on Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;

(iv) The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years; (2)

(v) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard. (3)

(vi) At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

(vii) All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned;

(viii) The NHAI shall provide funds for establishment and operation of a forest nursery having capacity to raise 1 lakh plants per annum in each of the forest division through which the road is passing, for distribution of seedling to local villagers at concessional rates. Location of nurseries will be identified before grant of stage-II approval.

(ix) The user agency shall raise and pay the cost of strip plantation on either side of the road and central verge, as per IRC specification, with maintenance of 5 years.

(x) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

(xi) The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

(xii) The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

(xiii) No labour camp shall be established on the forest land;

(xiv) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.

(xv) The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

(xvi) The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

(xvii) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

(xviii) The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area;

(xix) Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;

(xx) The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost.

(xxi) The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 in support thereof.

(xxii) Any other condition that the Addl. PCCF (Central), Regional Office, Lucknow may stipulate from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xxiii) The user agency shall submit the annual compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the Regional Office, Lucknow regularly; and

(xxiv) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

3. After receipt of the compliance report on the fulfillment of the above mentioned conditions contained in Para 2 above, from the State Government of Uttar Pradesh, formal approval will be considered in this regard under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The transfer of forest land to the User Agency shall not be affected by the State Government till formal orders approving the diversion of forest land are issued by the Central Government.

Yours faithfully,

(H. C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow.
3. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard file.

(H. C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests